परेशानी : फीस नहीं भर पाने से पढ़ाई छोड़ने की नौबत

आय की सीमा बढ़ी, फिर भी लाभ से वंचित मेधावी छात्र

XPOSE
हॉट इश्यू

अभिषेक वर्मा

xpose.indore@epatrika.com

इंदौर. प्रदेश के होनहार छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए बनी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की पात्रता होने के बाद भी हजारों छात्र लाभ से वंचित हैं। फीस नहीं भर पाने से कई पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। सरकार ने योजना के लिए अभिभावकों की सालाना आय 6 से बढ़ाकर साढ़े सात लाख रुपए भी की, लेकिन इस सत्र में एडमिशन लेने वालों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा।

2017-18 सत्र से शुरू हुई योजना में सरकारी और अनुदान प्राप्त कॉलेज में एडमिशन लेने वाले ऐसे छात्र जिन्हें 12वीं में एमपी बोर्ड से 70 फीसदी और सीबीएसई या अन्य बोर्ड से 85 फीसदी अंक मिले, उनकी फीस नहीं लगेगी। पात्रता के लिए अभिभावक की सालाना आय 6 लाख रुपए से कम होना थी। पहले दो साल इस योजना में एडमिशन लेने वालों में से कई छात्रों के अभिभावकों की सालाना आय अब 6 लाख से पार होने से उनकी राशि अटक गई। ऐसे छात्रों को राहत देने तकनीकी शिक्षा विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार कर आय पात्रता साढ़े सात लाख रुपए सालाना कर फीस की 75 फीसदी राशि मंजूर करने का निर्णय लिया। इससे 2017-18 और 2018-19 के सत्र में एडमिशन लेने वालों को भले ही राहत मिली मगर 2019-20 वाले इससे वंचित हो रहे हैं। इनमें आरक्षित वर्ग के वे छात्र भी हैं, जो शासन की स्कॉलरशिप की पात्रता रखते थे, लेकिन मेधावी योजना में लाभ की पात्रता की उम्मीद में इन्होंने स्कॉलरशिप के भी आवेदन नहीं किए। छात्र अफसरों से गुहार लगा रहे है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है।

मुख्यमंत्री
मेधावी विद्यार्थी
योजना

"शासन का आदेश स्पष्ट है। एडमिशन के समय जिनके परिवार की सालाना आय 6 लाख तक थी, उन्हें मेधावी योजना का लाभ मिलेगा। आय बढ़कर साढ़े सात लाख सालाना होने तक फीस की 75 फीसदी राशि दी जाएगी। कोर्ट के 100 फीसदी भुगतान के आदेश पर शासन ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

संतोष गांधी, नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना

कोर्ट ने दिए 100 फीसदी फीस के आदेश

सालाना आय 6 से साढ़े 7 लाख रुपए वालों की 75 फीसदी फीस का भुगतान का आदेश सरकार को बदलना पड़ सकता है। शासन ने 4 फरवरी को आदेश जारी किया, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट ने आइआइटी के छात्र की याचिका पर आदेश दिया कि योजना में एडमिशन लेने वालों की 100 फीसदी राशि शासन ही देगा। दरअसल, योजना में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि 6 लाख रुपए से ज्यादा आय होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा या 75 फीसदी ही लाभ मिलेगा।

दोहरा रवैया क्यों ?

इस सत्र में मेधावी योजना में बीटेक एडमिशन लेने वाले अनुराग कौशल के परिवार की सालाना आय साढ़े 6 लाख रुपए है। अनुराग का कहना है कि सरकार हर सत्र के लिए अलग-अलग नियम बनाकर दोहरा रवैया अपना रही है। अगर पिछले सत्र में एडमिशन लेने वालों को अब साढ़े सात तक आय होने पर लाभ मिल रहा है तो इस सत्र में एडमिशन लेने वालों का क्या कसूर है। इसी तरह संबल से एमटेक में एडमिशन लेने वाले मोहित पटेल ने कहा, फीस भरने की स्थिति नहीं होने पर संबल में प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया था। पहले पता चल जाता कि सरकार से मदद नहीं मिलेगी तो सरकारी कॉलेज ही चुन लेता। दो साल पढ़ने के बाद कॉलेज की फीस जमा करने के पैसे कहां से लाएं।

संबल वालों को भी नहीं मिल रहा सहारा

संबल योजना में एडमिशन लेने वाले कई छात्रों को भी अब सहारा नहीं मिल पा रहा है। दरअसल, शासन ने मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के तहत संबल में पंजीकृत परिवार के छात्रों को भी सरकारी और अनुदान प्राप्त कॉलेजों में सिर्फ एक रुपए फीस पर एडमिशन दिए थे। मगर, एमसीए-एमटेक सहित कई तरह के कोर्स में एडमिशन लेने वालों के आवेदन अब नहीं लिए जा रहे। फीस नहीं भर पाने से ये छात्र भी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं।

शा. नूतन स्कूल में कलेक्टर ने किया टिंकरिंग लैब का शुभारंभ

मूविंग रोबोट्स देख कलेक्टर बोले- हर सरकारी स्कूल में बने ऐसी लैब

पत्रिका लाइव रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. स्कूली विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब का प्रयोग शुरू किया है। इसके तहत शहर के शासकीय नूतन हा.से. स्कूल में अत्याधुनिक लैब तैयार की गई। शुक्रवार को कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने इसका शुभारंभ किया। रोबोटिक्स लैब के उपकरण और विद्यार्थियों द्वारा तैयार रोबोट देख उन्होंने कहा, अन्य सरकारी स्कूलों में इस तरह की रोबोटिक्स लैब बने। शहर के ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूल इसका प्रस्ताव तैयार कर बताएं। स्कूल प्रस्ताव बनाकर मुझे लिखकर दें कि उनके स्कूल में टिंकरिंग लैब क्यों बनाई जाए।

मालूम हो, पहले चरण में एनडीएमसी के तहत आने वाले दिल्ली के 15 स्कूल में ऐसी लैब बनी हैं। इसके बाद अलग-अलग राज्यों को तीन हजार स्कूलों को अटल टिंकरिंग लैब के लिए चुना गया। पहले चरण में इंदौर के तीन निजी और दो सरकारी स्कूल भी शामिल थे। जिले में करीब 6 महीने पहले स्वीकृति मिलने के बाद नूतन स्कूल में टिंकरिंग लैब बनाने की शुरुआत की गई। यहां मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों से नई पीढ़ी को रूबरू कराया जा रहा है। महीनेभर के भीतर ही लैब में 20 से ज्यादा साइंस के प्रोजेक्ट, मॉडल बनाए जा चुके हैं। विद्यार्थियों ने दो मूविंग रोबोट भी इसी लैब में तैयार किए। शुभारंभ अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी, राजेंद्र मकवाना, डीपीसी अक्षय सिंह राठौड़, प्राचार्य मनोज खोपकर सहित स्कूल स्टाफ व शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।